प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

01-अप्रैल-2016 17:17 IST

गोल्ड मुद्रीकरण योजना संभावित जमाकर्ताओं के लिए इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए उदारतापूर्वक।

सरकार ने 5 नवंबर, 2015 को गोल्ड मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) लॉन्च की थी। इसके बाद लोगों द्वारा सोने के मुद्रीकरण की सुविधा के लिए इस योजना में कई संशोधन किए गए हैं। इस योजना को 31 मार्च, 2016 को और संशोधित किया गया है।

अब, मध्यम और दीर्घकालिक सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) के तहत जमा सोने के लिए, परिपक्वता पर प्रिंसिपल का रिडेम्प्शन जमाकर्ता के विकल्प पर, रिडेम्प्शन के समय जमा राशि के मूल्य के बराबर भारतीय रुपया में होगा या सोने में। जहां जमा की छूट सोने में है, आईएनआर के मामले में धारणात्मक रिडेम्प्शन राशि के 0.2% की दर से एक प्रशासनिक शुल्क जमाकर्ता से एकत्र किया जाएगा। हालांकि, एमएलटीजीडी पर अर्जित ब्याज की गणना जमा के समय भारतीय रुपये के संदर्भ में सोने के मूल्य के संदर्भ में की जाएगी और केवल नकदी में ही भुगतान किया जाएगा।

यह उम्मीद की जाती है कि उपरोक्त संशोधन संभावित जमाकर्ताओं के लिए योजना को अधिक आकर्षक बना देगा।

*****

एमएएम / KA / ए